viuh ckr

तिब्बत में दलाई लामा के चित्रों पर प्रतिबंध जारी

तिब्बत में परमपावन दलाई लामा जी की तस्वीरों पर चीन सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध वर्षों से जारी है। यह खबर बेबुनियाद है कि इस प्रतिबंध को चीन सरकार ने समाप्त कर दिया है। चीन सरकार का यह एक नया हथकंडा है। उसकी ओर से लोगों को गुमराह करने के लिए उड़ाई गई यह अफवाह है। वास्तविकता यह है कि चीन सरकार की नज़र में तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा जी अवांछनीय तत्व हैं। वे तिब्बत की आजादी की मांग करने वाले, इसके लिए तिब्बतियों को भड़काने वाले तथा विश्वस्तर पर स्वतंत्र तिब्बत के पक्ष में समर्थन जुटाने वाले तथाकथित देशद्रोही हैं। तिब्बत पर अपने अवैध नियन्त्रण के समय से ही चीन की सरकार दलाई लामा को इसी नज़रिये से देखती आ रही है। स्वतंत्र तिब्बत देश पर अवैध कब्जा करने वाला चीन देशभक्त तिब्बतियों को ही देशद्रोही बता रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे।

नई अफवाह उड़ाकर चीन की सरकार तिब्बत की दयनीय स्थिति के संबंध में तिब्बत समर्थकों को भ्रमित कर रही है। तिब्बत में विचलित करने वाली आत्मदाह की दुखद घटनायें अब भी जारी हैं। चीन सरकार द्वारा तिब्बत में जारी हिंसक उत्पीड़न के खिलाफ पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करने और दलाई लामा की तिब्बत में ससम्मान वापसी तथा तिब्बत की आजादी की मांग करते हुए गत कुछ ही महीनों में अनेक तिब्बती आत्मदाह के जरिये शहीद हो चुके हैं। आत्मदाह की घटनाओं से चीन की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई है। वह इन घटनाओं के लिए भी दलाई लामा को दोषी ठहराता रहा है। सच्चाई है कि तिब्बती लोग चीन सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार से तंग आकर आत्मदाह के लिए बाध्य हो रहे हैं। दलाई लामा जी तो स्वयं तिब्बतियों से आत्मदाह नहीं करने की अपील कर रहे हैं। तिब्बतियों के आत्मदाह की खबरों से वे स्वयं व्यथित हैं। ऐसी दंश में चीन सरकार द्वारा उड़ाई गई अफवाहों से हमें सचेत रहना होगा।

अभी 06 जुलाई 2013 को दलाई लामा जी के 78वें जन्मदिन के अवसर पर विश्वभर में तिब्बत समर्थकों द्वारा अनेक भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गये। इस अवसर पर दलाई लामा ने लोगों से करूणा एवं भाइचारे की अपील की है, जिससे सभी सुखी, शांत तथा सुरक्षित रहकर संपूर्ण समाज का कल्याण करें। ऐसे आयोजन तिब्बत में भी किए गये, जहाँ अनेक तिब्बतियों को चीन की सरकार ने बेरहमी से मारा–पीटा, क्योंकि वे दलाई लामा के दीर्घ जीवन हेतु पूजा–प्रार्थना कर रहे थे। चीन का यह है असली चेहरा।

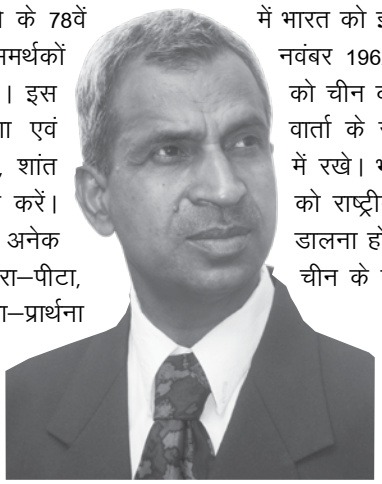

कर्णाटक के बायलाकुप्पी में आयोजित दलाई लामा के जन्म दिवस समारोह में तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमन्त्री डॉ. लोबजंग संग्ये, कर्णाटक के मुख्यमन्त्री तथा वहाँ के अनेक मंत्री एवं अधिकारी भी शामिल हुए। उसमें विभिन्न संप्रदायों के प्रमुख गुरू भी सम्मिलित थे। इस प्रकार यह कार्यक्रम सांप्रदायिक सद्भाव, करूणा, मैत्री, अंहिसा तथा पर्यावरण एवं प्रकृति के संरक्षण का कार्यक्रम हो गया। दलाई लामा जी तथा निर्वासित तिब्बत सरकार इन्हीं आदर्शों के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं।

निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमन्त्री डॉ. लोबजंग संग्ये ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी को हाल ही तीन लाख रूपये सहायतार्थ सौंपे हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में रह रहे तिब्बतियों ने भी दो लाख से अधिक रूपये इसी हेतु दिए हैं। इससे प्रमाणित होता है कि भारत में रह रहे तिब्बती हम भारतीयों के समान ही हमारे दुख–सुख में शामिल हैं। उत्तराखंड, विशेषकर केदारनाथ क्षेत्र में हुए व्यापक विनाश से तिब्बती भी दुखी हैं। इस विनाश का मुख्य कारण प्रकृति, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का मानव द्वारा किया जा रहा भोगवादी विनाश है। इस प्रकार की प्राकृतिक विपत्ति से बचने का उपाय है प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण करते हुए विकास। उत्तराखंड की प्राकृतिक विपदा के लिए चीन भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि उत्तराखंड से सटे तिब्बत में वह बड़े पैमाने पर पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद कर रहा है। तिब्बत और चीन के लोगों की प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति समझ में यही मौलिक अंतर है। प्रकृति से ''सहयोग'' बनाम ''संघर्ष'' का अंतर।

चीन के साम्राज्यवादी रूख से भारत को सदैव सावधान रहना होगा। गत जून 2013 में भी चीन ने भारत के लद्दाख क्षेत्र में घुसपैठ की है। उसने भारतीय सैनिकों के बंकर तोड़ दिए हैं। वहां लगे कैमरे और लाइट तोड़ दिए हैं। भारत सरकार को चाहिये कि वह चीन की उपनिवेशवादी आक्रामक नीति को नियंत्रित करे। ''हिन्दी–चीनी भाई–भाई'' के मायाजाल से भारत को निकलना ही होगा। वर्ष 1962 में भारत को इससे भारी धोखा हुआ है। हमें भारतीय संसद के 14 नवंबर 1962 के सर्वसम्मत प्रस्ताव के अनुरूप भारतीय भूभाग को चीन के चंगुल से मुक्त कराना है। चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के समय भारत सरकार उस प्रस्ताव को बराबर ध्यान में रखे। भारत के सभी राजनीतिक दलों तथा अन्य संगठनों को राष्ट्रीय हित में भारत सरकार पर इस हेतु उचित दबाव डालना होगा। तभी भारत सरकार का मनोबल बढ़ेगा और वह चीन के सामने दृढ़ता का परिचय दे सकेगी। ◆

प्रो० श्यामनाथ मिश्रा
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी
(राज.)
E-mail :- shyamnathji@gmail.com

तिब्बत समस्या का राजनीतिक हल होना चाहिएः संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त सुश्री नवी पिल्लई

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 3 जुलाई, 2013)

संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार अधिकारी ने 28 जुलाई को तिब्बत के हालात पर गहरी चिंता जताई और कहा कि वहां मानवाधिकारों की दुःखद स्थिति का राजनीतिक हल निकालना चाहिए। बीबीसी वर्ल्ड के हैव योर से प्रोग्राम में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त सुश्री नवी पिल्लई ने चीन सरकार से यह आह्वान किया कि वह तिब्बतियों की शिकायतों की जांच करे और उनका समाधान निकाले।

इस सवाल पर कि आखिर संयुक्त राष्ट्र तिब्बती जनता की पीड़ा का समाधान करने में असमर्थ क्यों है, सुश्री पिल्लई ने कहा कि तिब्बत की परिस्थिति के लिए राजनीतिक समाधान चाहिए। चीन का नजरिया यह है कि तिब्बत में मानवाधिकारों के बारे में उठाए जाने वाले सवालों के पीछे राजनीति होती है और दुनिया को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि तिब्बती जनता चीन के शासन के तहत अपनी नियति से पूरी तरह से संतुष्ट है।

इसके बावजूद, सुश्री पिल्लई ने अपनी चिंता को दोहराते हुए कहा, "मैंने ऐसे कई सार्वजनिक बयान जारी कर चीन से यह कहा है कि वह इसे सुरक्षा के मामले की तरह न देखे बल्कि तिब्बतियों की पीड़ा की असल वजह जानने की कोशिश करे और इसका भी पता लगाए कि वे आखिरकार विरोध के लिए आत्मदाह जैसे चरम कदम क्यों उठा रहे हैं।" गौरतलब है कि तिब्बत में चीनी शासन के विरोध में 2009 से अब तक कम से कम 119 तिब्बतियों ने आत्मदाह के रूप में विरोध प्रदर्शन किया है, जिनमें से ज्यादातर लोग स्वाधीनता और निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को वापस लाने की मांग कर रहे थे। चीन इसे इस बात के सबूत के रूप में देखता है कि आत्मदाह की घटनाओं में दलाई लामा का हाथ है।

सुश्री पिल्लई ने यह बात साफ कर दी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अगले अक्टूबर में जब चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा और जांच करेगा तो कहीं से भी मानक को घटाया नहीं जाएगा। पिल्लई ने कहा कि चीन ने उन्हें अपने यहां दौरे के लिए आमंत्रित किया है और वह निश्चित रूप से तिब्बत के हालात का जायजा लेने के लिए वहां जाएंगी। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि पिल्लई का तिब्बत दौरा कब होगा। ◆

नए रेल नेटवर्क से 2015 तक समूचे तिब्बत में 1.4 करोड़ चीनी आवाजाही करेंगे

(तिब्बतन रीव्यूडॉट नेट, 7 जुलाई)

वर्ष 2015 तक समूचे चीन के करीब 1.4 करोड़ लोग विरल जनसंख्या वाले तिब्बती पठार में आवाजाही (यात्रा) करने लगेंगे। यह यात्रा असल में उस नए रेल नेटवर्क के तैयार होने के बाद संभव होगी जिसके तहत कई नए रेलमार्गों का निर्माण हो रहा है या कई उनके बनाए जाने की योजना है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ ने 6 जुलाई को यह खबर दी है। खबर में कहा गया है कि चीन की 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (वर्ष 2011–2005) क्विंघई–तिब्बत रेलवे का विस्तार सभी दिशाओं में किया जाएगा, इस तरह तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र (टीएआर) के दक्षिणी हिस्से में किसी रेलमार्ग न होने का इतिहास खत्म हो जाएगा और पड़ोसी प्रांतों के साथ इसका संपर्क और मजबूत होगा।

फिलहाल चीन के क्विंघई प्रांत की राजधानी शीनिंग और तिब्बत की राजधानी ल्हासा के बीच करीब साल साल पुरानी 1956 किमी. लंबी रेल लाइन है। इस सेवा के द्वारा वर्ष 2012 में 1.07 करोड़ लोगों का परिवहन और 5.60 करोड़ टन माल की ढुलाई की गई। लेकिन इस रेलमार्ग का विस्तार पूरा होने के बाद क्विंघई–तिब्बत रेल कंपनी को उम्मीद है कि वर्ष 2015 तक उसके द्वारा 1.4 करोड़ लोगों की आवाजाही और 90 टन माल की ढुलाई की जाएगी। खबर के अनुसार कंपनी के वायस जनरल मैनेजर छू जियानपिंग ने कहा कि यह रेल नेटवर्क पश्चिमी चीन के बड़े शहरों को टीएआर के करीब ले आएगा। विस्तार की योजना के मुताबिक 253 किमी. लंबा रेलमार्ग दक्षिणी टीएआर में ल्हासा को शिगास्ते

के साथ जोड़ेगा, जो इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। टीएआर के दक्षिण–पूर्वी हिस्से में ल्हासा से निंगत्री तक एक नया रेलमार्ग पिछले कई साल से बनाया जा रहा है। निंगत्री भारतीय सीमा के करीब है।

इसी तरह क्विंघई प्रांत के गोलमुड शहर से भी दो नए रेलमार्ग शुरू किए जाएंगे। गोलमुड क्विंघई–तिब्बत रेलमार्ग पर एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। एक रेलमार्ग उत्तर–पश्चिम चीन के गांसू प्रांत के डनहुआंग की ओर जाएगा, जबकि दूसरा, उइगर स्वायत्तशासी क्षेत्र के शीक्यांग प्रांत के कोरला में जाएगा। करीब 12.9 अरब युआन की लागत से बनने वाला गोलमुड–डनहुआंग रेलमार्ग का निर्माण पिछले अक्टूबर में ही शुरू हुआ था और इसके पांच साल में पूरा होने की उम्मीद है। यह उस मौजूदा रेलमार्ग से जुड़ेगा जो शीक्यांग को क्विंघई और गांसू प्रांतों से जोड़ता है, इस तरह इसके पूरा होने पर एक वृत्तीय रेल नेटवर्क बन जाएगा। करीब 33.5 अरब युआन की लागत से बनने वाले 1,222.9 किमी. लंबे गोलमुड–कोरला रेलमार्ग का व्यवहार्यता परीक्षण जून माह में किया जा चुका है और इससे टीएआर और शीक्यांग के बीच सीधा रेल यातायात हो जाएगा, जिससे ल्हासा और उरुमकी के बीच दूरी 1,000 किमी. कम हो जाएगी। इसके अलावा क्विंघई प्रांत की सरकार ने सिचुआन प्रांत की राजधानी एवं आर्थिक केंद्र चेंगदू और क्विंघई प्रांत के गोलमुड एवं शीनिंग शहरों को जोड़ने के लिए दो नए रेलमार्ग बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसी तरह चीन सरकार पहले यह भी कह चुकी है कि नेपाल सरकार द्वारा बार–बार किए जाने वाले इस अनुरोध पर वह सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है कि तिब्बत रेल नेटवर्क का विस्तार उसकी सीमा तक और राजधानी काठमांडू तक किया जाए। सरकार पहले पाकिस्तान तक भी एक सामरिक रेल संपर्क बनाने की बात कर चुकी है। ◆

दलाई लामा के जन्म दिन पर प्रार्थना कर रहे तिब्बतियों पर चीनी पुलिस ने की फायरिंग से नौ तिब्बती घायल

न्यात्सो मठ के भिक्षु टाशी सोनम के सिर में गोली लगी है। उनका प्रशासनिक क्षेत्र की राजधानी डार्टसेडो (चीनी में कांगडिंग) के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 9 जुलाई)

गत 6 जुलाई को चीन के सिचुआन प्रांत के कार्जे (गांजी) प्रशासनिक क्षेत्र स्थित ताउ काउंटी में एक पवित्र पहाड़ी पर दलाई लामा का 78वां जन्म दिन मनाने के लिए जुटी हजारों की भीड़ पर चीन के अद्धसैनिक पुलिस द्वारा खुलेआम फायरिंग करने से कम से कम नौ तिब्बती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें से दो लोगों की हालत गंभीर है, जिनमें से एक भिक्षु हैं जिनके सिर में गोली लगी है और एक आम आदमी हैं जिनके शरीर में कम से कम आठ गोली लगी है। खबरों के मुताबिक उस दिन पवित्र और लोकप्रिय माछेन पोमर देवता की पहाड़ी पर न्यात्सो मठ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों तथा गेदेन छोलिंग भिक्षुणी मठ की भिक्षुणियों के साथ सैकड़ों आम तिब्बती प्रार्थना में शामिल हुए थे। लेकिन जब तिब्बती दलाई लामा की तस्वीर के सामने अगरबत्तियां सुलगाने और प्रार्थना का ध्वज लगाने की तैयारी ही कर रहे थे, चीनी जन सशस्त्र बल के सैकड़ों जवान वहां पहुंच गए और पूरे स्थान को घेर लिया। पुलिस ने वहां पहले से पहुंचे लोगों से घर जाने को कहा और जो लोग वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे उन्हें रोक दिया गया। भिक्षुओं ने सुरक्षा बलों को समझाने का प्रयास किया लेकिन जवानों ने उन्हें झिड़क दिया। तिब्बती उस स्थान से जाने से इनकार करते रहे और अन्य तिब्बती वहां पहुंचने की कोशिश करते रहे जिससे कुपित चीनी पुलिस ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया और अचानक वहां गोलीबारी शुरू कर दी।

चीनियों की बर्बरता के बीच ही न्यात्सो मठ के भिक्षु जांगछुप दोरजी ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। प्राप्त जानकारी के अनुसार वे उन्हीं भिक्षुणी पालदेन छोएत्सो के छोटे भाई हैं जो 3 नवंबर, 2011 को आत्मदाह कर शहीद हो गई थीं। चीनियों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके, उनके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और उन्हें गोली मार दी। यह सब खत्म होने के बाद देखा गया कि न्यात्सो मठ के भिक्षु टाशी सोनम के सिर में गोली लगी है। उनका प्रशासनिक क्षेत्र की राजधानी डार्टसेडो (चीनी में कांगडिंग) के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है,

जहां कई अन्य घायल तिब्बती भर्ती हैं। कम से कम आठ गोलियों को अपने शरीर में सहन करने वाले आम आदमी उग्येन टाशी की हालत ज्यादा गंभीर है और उन्हें प्रांतीय राजधानी चेंगदू ले जाया गया है। कई अन्य भिक्षुओं को गोली लगी है जिनमें जांगछुप दोर्जे, लोबसांग और सेरिंग धोनढुप शामिल हैं, ये सभी न्यात्सो मठ के हैं। एक भिक्षुणी को भी गोली लगी है जिनकी पहचान डोलमा के रूप में हुई है। वे मूलतः डनके नौमैड शिविर से हैं। गोली से घायल आम लोगों में खोरो नौमैड शिविर के टाशी, डुक्या नौमैड शिविर के नेंडक और क्यासोर नौमैड शिविर के सांगपो शामिल हैं। खबरों के अनुसार चीनी सुरक्षाकर्मियों ने तिब्बतियों की भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे, बहुत लोगों की पिटाई की गई, उन पर पत्थरों की बारिश की गई और भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों को ढोकर लाने वाले पहाड़ की तलहटी में खड़े वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। बहुत से तिब्बतियों को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। हिंसक दमन के बाद चीनी अधिकारियों ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त कर दी और न्यात्सो मठ पर कड़ा पहरा बिठा दिया गया। मठ के अधिकारियों और सुरक्षा बलों के बीच बातचीत के बाद बाद में तनाव कुछ दूर हुआ।

इस तरह की अफवाह उड़ी थी कि चीन ने हाल में क्विंघई और सिचुआन प्रांत के कुछ इलाकों में प्रायोगिक तौर पर दलाई लामा के लिए प्रार्थना जैसे धार्मिक आयोजन करने की कुछ छूट दी है, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग ने इसको सिरे से खारिज करते हुए खारिज किया है। इससे गोलीबारी की घटना को लेकर बना भ्रम दूर हो जाता है। धर्मशाला स्थित तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र के अनुसार कार्यक्रम का बर्बरता से दमन के बाद नित्सो मठ पहुंची सशस्त्र पुलिस ने इसके लिए माफी मांगी और आश्वासन दिया कि मृतकों के परिवारों या शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की वे जिम्मेदारी उठाएंगे। ◆

चीनी जनरल ने सीमा मसले पर भारत को चेतावनी दी

(तिब्बतन रीव्यू नेट, 5 जुलाई, 2013)

भारत के रक्षा मंत्री श्री ए. के. एंटोनी के 4 जुलाई को बीजिंग पहुंचने से पहले एक युद्धोन्मादी चीनी जनरल ने भारत को यह चेतावनी दी कि वह अधिकृत तिब्बत के पार विवादित सीमा के बारे में कुछ बोलने और करने से पहले काफी सचेत रहे। पीटीआई की 5 जुलाई की खबर के अनुसार लद्दाख में चीनी पीएलए जवानों की घुसपैठ के बाद नए सिरे से विश्वास बहाली के उपाय करने के लिए एंटनी चीन पहुंचे थे। चीनी सैनिकों की एक टुकड़ी द्व ारा भारतीय सीमा में घुसपैठ से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा हुआ था और यह करीब 20 दिनों तक चला था।

एंटनी पिछले सात वर्षों में चीन की यात्रा करने वाले पहले रक्षा मंत्री हैं। उन्हें चीनी रक्षा मंत्री जनरल चांग वांगक्युआन से 5 जुलाई को आधिकारिक वार्ता करनी थी। खबर के अनुसार सीमा में घुसपैठ, सीमा प्रतिरक्षा समन्वय समझौता (बीडीसीए) को अंतिम रूप देना (चीन द्वारा सीमा पर सुरक्षा के लिए सुझाई गई नई व्यवस्था), सीमा क्षेत्र के लंबित विवादों का अंतिम तौर पर निपटान आदि एंटनी के वार्ता के शीर्ष एजेंडे पर थे। एंटनी के प्रधानमंत्री ली केक्यांग से मिलने की संभावना है, हालांकि, राष्ट्रपति और चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी या नहीं, यह बात साफ नहीं हो पाई है।

एंटनी के अपने तीन दिवसीय चीन दौरे के लिए शंघाई में कदम रखने से कुछ ही घंटे पहले चीन की सामरिक संस्कृति प्रोत्साहन संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष और महासचिव मेजर जनरल लुओ युआन ने बीजिंग में विदेशी संवाददाताओं से बात करते हुए भारत को इस बारे में चेतावनी दी कि वह "कोई नई समस्या" न खड़ी करे। लुओ ने कहा, "भारतीय पक्ष को कोई नई समस्या नहीं खड़ी करनी चाहिए। उन्हें सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों की तैनाती बढ़ाकर नई समस्या शुरू करने से बचना चाहिए।"

लुओ ने कहा, "इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि चीन और भारत के बीच तनाव और समस्याएं हैं, खासकर सीमावर्ती इलाकों में। अब भी समस्या यह है कि भारतीय पक्ष ने 90,000 वर्ग किमी. जमीन कब्जा रखा है। ये समस्याएं हमें इतिहास से मिली हैं और हमें इन पर ठंडे दिमाग से विचार करना होगा।" उन्होंने अप्रैल में लद्दाख के देपसांग घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को तवज्जो न देते हुए कहा, "इस मसले को मीडिया ने हवा दिया है और मीडिया कई बार समस्याओं को बढ़ा–चढ़ा कर दिखाता है।"

यह आरोप लगाते हुए कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो यह कहता है कि वह चीन के खतरे की वजह से अपनी सैन्य क्षमता का विकास कर रहा है, लुओ ने कहा, "भारत को इस बारे में सचेत रहना चाहिए कि वह क्या कहता है और क्या करता है।"

असल में भारत का कहना है कि वह चीन द्वारा अधिकृत तिब्बत में तैयार किए गए सामरिक बुनियादी ढांचे, सेना की तैनाती और अन्य क्षमता के विकास की संयत तरीके से बराबरी करने की कोशिश ही कर रहा है।

लुओ ने चीनी पीएलए के पाकिस्तान की सेना से भी करीबी रिश्तों का बचाव किया। उन्होंने कहा, "इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन और पाकिस्तान के बीच परंपरागत मित्रता है और हमारा पाकिस्तान के साथ सदाबहार व्यापक सामरिक साझेदारी है।"

उन्होंने कहा, "हमारी भारत के साथ भी सामरिक साझेदारी है और हमें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान एकसाथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ रहेंगे जैसा कि सहअस्तित्व के पंचशील सिद्धांतों में कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान अपने मतभेद और समस्याएं शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाएंगे। लुओ को आल चाइना जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने विदेशी पत्रकारों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था। ◆

तिब्बत का भविष्य दलाई विरोधी लड़ाई के गहराने पर निर्भर करता है: चीन के एक शीर्ष नेता

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 11 जुलाई, 2003)

चीन के शीर्ष सात नेताओं में से एक ने 9 जुलाई को कहा कि अधिकृत तिब्बत में स्थायी समृद्धि और स्थिरता का आधार यह है कि उससे लड़ाई जारी रखी जाए जिसे वे "14वें दलाई का गुट" कहते हैं और स्थानीय जनता की जीविका में बढ़ोतरी की जाए। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ की 9 जुलाई की खबर के अनुसार परंपरागत तिब्बती प्रांत कानल्हो (जो अब चीन के गांसू प्रांत में एक प्रशासनिक क्षेत्र है) में पार्टी की पोलित ब्यूरो के स्थायी समिति के सदस्य श्री यू झेंगसेंग ने आरोप लगाया कि दलाई लामा "लंबे समय से अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त हैं जो विभिन्न नस्लीय समूहों और तिब्बती बौद्ध परंपरा दोनों के खिलाफ है। खबर के अनुसार यु ने "राष्ट्रीय एकीकरण और तिब्बत क्षेत्र के विकास एवं स्थिरता के लिए दलाई लामा गुट के खिलाफ पूरी तरह जंग" का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तिब्बत के मसले को हल करने के लिए दलाई लामा के "मध्यम मार्ग" का प्रस्ताव चीन के संविधान और उसके क्षेत्रीय नस्लीय स्वायत्तता से सीधे टकराता है।

यु की टिप्पणी तिब्बत से आने वाली उन खबरों को मिथ्या साबित करती है जिनमें कहा गया था कि क्विंघई और सिचुआन प्रांत के कुछ हिस्सों और ल्हासा के गादेन मठ में तिब्बतियों को प्रायोगिक आधार पर खुलकर दलाई लामा के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का मौका दिया जा रहा है और उनकी तस्वीर रखने की भी इजाजत दी जा रही है, बशर्ते कि उनको धार्मिक नेता की तरह पेश किया जाए। रॉयटर्स ने 9 जुलाई को बताया है कि शिनहुआ की चीनी भाषा की खबर के अनुसार यु ने कहा, "राष्ट्रीय एकता और तिब्बती इलाके में स्थिरता के लिए हमें एक साफ रवैया अपनाना होगा और दलाई गुट के खिलाफ संघर्ष गहराना होगा।"

यु चीन की जन राजनीतिक परामर्शकारी सम्मेलन (सीपीपीसीसी) के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने यह मांग की कि तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा से साफ दूरी बनाए रखें और किसी भी अलगाववादी कार्रवाई का सख्ती से विरोध करें जो सीपीसी के शासन और समाजवादी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता हो। दलाई लामा ने बार–बार इस बात पर जोर दिया है कि वह तिब्बत की आज़ादी नहीं बल्कि चीनी संविधान के तहत उसके लिए केवल स्वायत्तता चाहते हैं। लेकिन यु ने कहा, "केवल जब दलाई लामा सार्वजनिक तौर पर खुलकर यह घोषणा कर देंगे कि तिब्बत चीन का अभिन्न हिस्सा है, 'तिब्बत की स्वतंत्रता' का विचार छोड़ देंगे और अपनी अलगाववादी गतिविधियों को रोक देंगे, तभी सीपीसी की केंद्रीय समिति से उनके रिश्ते सुधर सकते हैं।" शिनहुआ के अनुसार यु ने यह टिप्पणी एक स्थानीय प्राइमरी स्कूल के दौरे के बाद की। वह धार्मिक संगठनों और नस्लीय अल्पसंख्यकों के मामले देखने वाले चीन के शीर्ष अधिकारियों में से हैं। उन्होंने कहा कि नस्लीय अल्पसंख्यक क्षेत्रों में द्विभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने से विद्यार्थियों को भविष्य में रोजगार तलाशने में मदद मिलेगी और इससे विभिन्न नस्लीय समूहों में परस्पर समझ बढ़ेगी। चीन का दावा है कि नस्लीय अल्पसंख्यक स्कूलों में विद्यार्थियों को चीन की द्विभाषी शिक्षा के तहत चीनी और तिब्बती दोनों माध्यमों में पढ़ाया जाता है। हालांकि, सच्चाई यह है कि तिब्बती भाषा को तिब्बती स्कूलों में सिर्फ एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, जबकि अन्य सभी विषय चीनी माध्यम में ही पढ़ाए जाते हैं। चीन के शीर्ष राजनीतिक सलाहकार के भी शियाहे काउंटी में स्थित लाबराग मठ में जाकर धार्मिक हस्तियों से मिलने की खबर है। उन्होंने धार्मिक पदाधिकारियों और भिक्षुओं को देशभक्त बने रहने की सलाह दी है। इस बीच ब्लूमबर्ग डॉट कॉम ने 9 जुलाई को खबर दी है कि चीन ने दलाई लामा की धार्मिक गुरु की हैसियत पर सवाल उठाए हैं। उसके अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ छुनयिंग ने बीजिंग में 9 जुलाई को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दलाई लामा कोई "निर्दोष धार्मिक नेता नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति हैं जो दीर्घकालिक स्तर पर चीन को बांट देंगे, समुदायों की एकता को खत्म कर देंगे और धर्म के नाम पर चीन की सामाजिक स्थिरता को नष्ट कर देंगे। ◆

तिब्बत के दु:खद हालात पर इटली के शहर में सम्मेलन का आयोजन

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 9 जुलाई)

इटली के तुरीन शहर में 5 जुलाई को "तिब्बत का परिदृश्य और भविष्य के लिए दृष्टिकोण" विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के वक्ताओं में वहां के पीडमोंट क्षेत्र के बोर्ड के चेयरमैन श्री वलेरियो कैटेनियो और धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती संसद के स्पीकर श्री पेनपा सेरिंग शामिल थे।

वक्ताओं में पीडमोंट क्षेत्र के कौंसिलर श्री गियामपियरो लियो शामिल थे। निर्वासित तिब्बती प्रशासन की वेबसाइट तिब्बत डॉट नेट की 8 जुलाई की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा, "यह सम्मेलन फिर इस पिमोंटे की एसेंबली की इस इच्छाशक्ति का प्रमाण है कि वह इन असाधारण लोगों के अधिकारों की रक्षा करना चाहती है। एक ऐसी समृद्ध संस्कृति जिसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जा रहा है।"

इस सम्मेलन में शामिल अन्य लोगों में फ्रांस की संसद के सीनेटर श्री एंड्रे गैटोलिन, इंटरग्रुप इटालियन पार्लियामेंट्री फॉर तिब्बत के पूर्व अध्यक्षगण श्री माटेओ मेकासी एवं श्री गियानी वरनेट्टी, तुरिन शहर की पार्षद श्रीमती मारियाक्रिस्टीना स्पिनोसा और रेडिकल एडेलेड एजिलेट्टा के श्री ब्रूनो मेलानो शामिल थे। इस सम्मेलन का आयोजन पिएमोंटे के रीजनल कौंसिल में एसोसिएशन फॉर तिब्बत और ह्यूमन राइट्स और इटली के तिब्बती समुदाय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ◆

‘असंतोष है तिब्बती आत्मदाह की वजह‘

कारोल जे. विलियम्स/लॉस एंजिल्स टाइम्स

वायस ऑफ अमेरिका के तिब्बती सेवा के डायरेक्टर लोबसांग ग्यात्सो द्वारा निर्मित एक घंटे लंबी डॉक्यूमेंट्री ‘फायर इन द लैंड स्नो‘‘ में तिब्बत के हाल के इतिहास पर नजर डाली गई है और यह सवाल उठाया गया है कि आखिर क्यों बहुत से लोग ‘‘मौत के लिए सबसे दर्दनाक और भयावह तरीका ‘‘अपना रहे हैं। यह दुनिया की छत कहे जाने वाले हिमालयी उच्च भूमि में रहने वाली जनता की एकजुटता के नवीनतम मुश्किलों वाले अध्याय को पेश करता है। ग्यात्सो ने फिल्म निर्माण और उसके संदेश के बारे में लास एंजिल्स टाइम्स से बात की।

loky% vkRenkg dh ?kVukvksa esa bruh rsth ls c<r D;ksa gks jgh gS\ D;k frCcfr;ksa ds vanj bl Hkkouk fodflr gks xbZ gS fd bl ds vykok vkSj fdlh pht ls nqfu;k dk /;ku vkdf"kZr ugha fd;k tk ldrk

X;kRlks% इसके पीछे कई वजहे हैं। पहला मठों सख्त कार्रवाई और बढ़ गई है और उनमें ‘‘पुनर्शिक्षा कार्यक्रम‘‘ चलाया जा रहा है। प्रशासन का रवैया यह है कि वे आत्मदाह करने वाले लोगों को हाशिए के और अपनी समस्याओं से परेशान लोग बताते हैं। इस तरह की छवि बनाने को तिब्बती अपने अपमान के रूप में देखते हैं क्योंकि वे इन्हें उन गंभीर मसलों की प्रतिक्रिया में ही कार्रवाई मानते हैं जिनका समाधान नहीं किया जा रहा।

loky% ftu yksxksa dh vkRenkg ls ekSr gks xbZ mudk 'kghn dh rjg xkSjokfUor fd;k tk jgk gSA dgha ,slk rks ugha fd vkRenkgksa dh la[;k c<us ds ihNs ;gh izsj.kk dke dj jgh gks

X;kRlks% इन सबको प्रेरणा मानना सामान्यीकरण होगा। कुछ इस वजह से किए गए हैं कि मठ जीवन और धार्मिक परंपरा पर हमला किया जा रहा गए है। कुछ आत्मदाह शिक्षा के माध्यम में बदलाव के विरोध में किए गए हैं। शिक्षण माध्यम के रूप में तिब्बती की जगह मंदारिन यानि चीनी भाषा को अपनाया जा रहा है। लगभग सभी ने समूचे तिब्बत में की जारी सख्त कार्रवाई में कुछ नरमी बरतने का आह्वान किया है। आत्मदाह करने वाले कुछ लोगों ने जो बयान छोड़े हैं—कविता या रिकॉर्डिंग के रूप में – उन सभी में स्वाधीनता और दलाई लामा को वापस लाने की मांग की गई है। मैं नहीं समझता कि तिब्बती समुदाय में आत्मदाह की भावना किसी तरह की सनक का रूप ले चुकी है। विरोध का यह तरीका शुरू होने से पहले लेखकों और कलाकारों और तिब्बती समुदाय ने ज्यादा परंपरागत तरीके से असंतोष जाहिर करने की कोशिश की थी।

loky% i=dkjksa dks vkerkSj ij frCcr esa ugha tkus fn;k tk jgk] vkius mls bykds dh rLohjsa dSls dSn dha

X;kRlks% इसमें बहुत मुश्किल आई। आत्मदाह या तिब्बत में सुरक्षा घेरे की आज जो भी तस्वीरें या वीडियो उपलब्ध हैं, उनका फिल्म में इस्तेमाल कि गया। यह तस्वीरें या वीडियो तिब्बत से कुछ लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर भेजी थीं। ये तस्वीरें मुख्यतः मोबाइल फोन से ली गई थीं। फिल्म के कुछ फुटेज में ल्हासा के बाहर एक सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दिख रहा है कि लोगों को पीटा जा रहा है। यह असल में चीनी सुरक्षा बलों द्वारा रिकॉर्ड वीडियो फुटेज है जो हम तक लीक की गई है।

loky% vkids D;k yxrk gS] phu T;knk [kqys vkSj Lok;Rr frCcr ls Mjrk gS

X;kRlks% इस फिल्म में यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश नहीं की गई है कि बीजिंग किस बात से डरता है। कुछ लोगों

की यह राय है कि शायद बीजिंग और तिब्बत में जो नेतृत्व है कि उनके बीच सही संपर्क सेतु नहीं है। यदि तिब्बत मसले पर वैधानिक प्रस्ताव आ जाए तो कई क्षेत्रीय नेताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह सोच कि वहां बाहरी ताकतों के उकसावे से एक अलगाववादी आंदोलन चलाया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार से फंड आ सके, असल में ऐसी सरकारी नीतियों को और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए है जिनसे तिब्बतियों में असंतोष बढ़ता है। यह सब एक चक्र है।

loky% D;k frCcrh phu ls vktknh pkgrs gSa

X;kRlks% दलाई लामा ने 1980 के दशक के मध्य में ही यह साफ कर दिया था कि वह तिब्बत के लिए आज़ादी नहीं चाहते हैं। वह एक ऐसी नीति चाहते हैं जिससे तिब्बत चीनी संविधान के भीतर लेकिन चीन राज्य से बाहर हो। ऐसे तिब्बत का अपने धार्मिक और भाषाई मामलों में बड़ा दखल होना चाहिए। यह कहना गलत होगा कि चीन के भीतर इस तरह के हल से सभी खुश होंगे, लेकिन वे दलाई लामा के इस रुख को स्वीकार करेंगे।

loky% nykbZ ykek 78 o"kZ ds gks pqds gSa vkSj vk/kh lnh ls Hkh T;knk le; rd frCcr ls ckgj jgs gSaA frCcfr;ksa ds fy, vxys vk/;kfRed usrk dks yksus dh D;k ;kstuk gS

X;kRlks% दलाई लामा ने कहा है कि वह उत्तराधिकार के तमाम विकल्पों पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि तिब्बत मसले का अस्तित्व उनसे इतर भी है और यह आगे भी जारी रहेगा।

loky% phuh 'kkldksa ds eqfLye mbxj] bZlkb;ksa vkSj Qkyqu xksx ckS) er dk ikyu djus okyksa ds lkFk vPNs fj'rs ugha gSaA D;k mueasa vYilañ[;d /keksZa ds izfr neu dh ,d lkekU; uhfr gS

X;kRlks% उइगर और कुछ अन्य संप्रदायों के भी हमारे जैसे कुछ साझे अनुभव हैं। लेकिन तिब्बत से कुछ अन्य मसले भी खड़े हुए हैं। यह एक समाज, राष्ट्रीयता और समूचा क्षेत्र है जिसका बीजिंग के साथ कभी समझौता हो चुका है और उसका शताब्दियों से एकीकृत अस्तित्व रहा है।

loky% frCcr esa fnu&izfr&fnu dk thou dSlk gS

X;kRlks% तिब्बती जनसंख्या का बड़ा हिस्सा ग्रामीण खेतिहर जीवन बिताता है। इस जनसंख्या का काफी बड़ा हिस्सा करीब 20 से 25 फीसदी परंपरागत रूप से नोमैड है। लेकिन पिछले एक दशक से नोमैड को काफी कठिन समय से गुजरना पड़ रहा है। उनके चारागाह बंद कर दिए

वायस ऑफ अमेरिका के तिब्बती सेवा के डायरेक्टर लोबसांग ग्यात्सो

गए हैं और उनको अपने जानवर बेचने को मजबूर कर कालोनियों में बसा दिया गया है। इस तरह से यह सिर्फ जीवन यापन का जरिया ही नहीं बल्कि पूरी एक जीवन पद्धति को खत्म कर देने जैसा है।

loky% phu dh eq[; ehfM;k us vkRenkg dh ?kVukvksa dks cgqr de doj s fn;k gSA vkidks D;k yxrk gS] ;fn phuh ukxfjdksa dks ;g tkudkjh gks fd frCcr esa neu gks jgk gS ftlls frCcfr;ksa dks fojks/k iznZkZu ds ,sls pje rjhds viukus iM+ jgs gSa rks mudh izfrfØ;k D;k gksxh

X;kRlks% इस परिस्थिति को सीसीटीवी पर जिस तरह से पेश किया गया है उससे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि औसत चीनी दर्शक आत्मदाह की घटनाओं को तिब्बतियों द्वारा किए जा रहे घृणित दंगों एक और उदाहरण ही मानता होगा। यदि उन तक इस बारे में जानकारी बिना किसी अवरोध के पहुंचे कि पिछले 50 साल में तिब्बत में क्या हुआ है, तिब्बतियों को किस तरह के सांस्कृतिक और मानवाधिकार मसलों का सामना करना पड़ रहा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चीनी लोग भी इस पर चिंता जताएंगे और इसके समाधान की मांग करेंगे।

loky% MkD;qesaVªh esa T;knkrj ftu lw=ksa ls ckr dh xbZ gS os frCcr ls ckgj ds gSaA os frCcr bykds esa gksus okyh xfrfof/k;ksa ij dSls utj j[krs gSa

X;kRlks% साल–दर–साल, महीने से महीने तक संचार के तरीके बदलते रहते हैं। आमतौर पर जिन लोगों ने फिल्म में बात की है वे अपने पेशे और जुनून के लिए तिब्बत में होने वाली घटनाओं की अद्यतन जानकारी रखते हैं। आपको ऐसे लोगों का समूह कम ही मिलेगा जो यह बता सकें कि चीन के भीतर क्या हो रहा है, जिस तरह से तिब्बत मसलों पर नजर रखने वाले लोग बताते हैं।

loky% djhc vk/kh vkcknh ls tks xfrjks/k cuk gqvk gS mlds nwj gksus dh vki D;k lEHkkouk ns[krs gSa\ D;k chftax vpkud gh frCcr ij uje #[k vf[r;kj dj ysxk

X;kRlks% आज तो ऐसे किसी हल की संभावना दूर–दूर तक नजर नहीं आती, यदि चीनी नेतृत्व कुछ साहस और दृष्टि दिखाए तो यह संभव हो सकता है। चीनी प्रशासन ने 1951 में जिस 17 बिंदुओं वाले समझौते पर दस्तखत किया था उनमें से बहुत से बिंदु दलाई लामा के उस प्रस्ताव जैसे ही हैं जिसमें उन्होंने तिब्बत के लिए चीनी राज्य के भीतर ही स्वायत्तता की बात कही है। इसलिए यदि बीजिंग मसले को सुलझाने में गंभीर लगा तो इस दुःसाध्य लग रहे समस्या का हल दूर की कौड़ी नहीं होगी। ◆

परमपावन दलाई लामा का 78वां जन्म दिन

dukVd d c;kydIih dLcs es fLFkr lsjk eB es xr 6 tqykbZ dks ijeikou nykbZ ykek ds 78osa tUe fnu lekjksgA

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 8 जुलाई)

कर्नाटक के बयालकुप्पी कस्बे में स्थित सेरा मठ में गत 6 जुलाई को परमपावन दलाई लामा के 78वें जन्म दिन समारोह में उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई देने वाले विशिष्ट अतिथियों में दो राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया और अरुणाचल के मुख्यमंत्री श्री नबाम तुकी ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता को व्यक्तिगत रूप से जाकर बधाई दी। इनके अलावा बधाई देने वालों में हिंदू, ईसाई और मुस्लिम धर्म के कई धर्मगुरु, कई मंत्री, सांसद एवं विधायक और दोनों राज्यों के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। निर्वासित तिब्बती प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार इस समारोह में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए।

समारोह को संबोधित करते हुए दलाई लामा ने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा उपहार यही होगा कि उनके शुभेच्छु लोग हर प्राणी के प्रति वास्तविक प्यार और करुणा दर्शाएं। एक खुशहाल मानवता सभी धार्मिक गुरुओं का साझा कर्तव्य है। उन्होंने कर्नाटक सरकार और जनता को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने राज्य में 40,000 से ज्यादा तिब्बतियों को शरण दिया है।

निर्वासित तिब्बती प्रशासन के प्रमुख सिक्योंग लोबसांग सांगे ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने तिब्बती जनता और समूची मानवता के लिए हासिल बहुत तरह की उपलब्धियों के लिए दलाई लामा की भूरि–भूरि प्रशंसा की। इस अवसर पर गेशे रोंगपो लोबसांग न्यांडक ने निर्वासित तिब्बती संसद का संदेश पढ़ा।

सिक्योंग ने अपने संबोधन में कहा कि तिब्बती स्कूलों में धर्मनिरपेक्ष नैतिक शास्त्र से जुड़ा पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। उन्होंने इस बात के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि तिब्बत मसले का हल निकालने के लिए मध्यम मार्ग नीति को और लोकप्रिय बनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस नीति को तिब्बत के भीतर रहने वाले कई प्रख्यात तिब्बती समर्थन दे रहे हैं, "क्योंकि उनका मानना है कि यह तिब्बत के मसले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का यथार्थवादी रवैया है।" हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया कि चीनी शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रमुख तिब्बतियों की बात कर रहे थे या वहां के सत्ता प्रतिष्ठान में शामिल हो चुके तिब्बतियों की।

उन्होंने यह भी कहा कि चीन के साथ वार्ता के लिए बना उनके प्रशासन के कार्यबल में विस्तार किया जाएगा और इसके सदस्यों की 26वीं बैठक सितंबर 2013 में होगी। चीन ने यह साफ किया है कि वह निर्वासित तिब्बती प्रशासन के साथ कोई वार्ता नहीं करना चाहता और दलाई लामा के साथ उनके व्यक्तिगत मसलों पर बातचीत की जा सकती है।

दलाई लामा का 78वां जन्म दिन धर्मशाला सहित समूचे आज़ाद दुनिया में रहने वाले तिब्बतियों द्वारा धूम–धाम से मनाया गया और धर्मशाला में मूसलाधार बारिश से भी आयोजन की भव्यता और गंभीरता पर कोई असर नहीं पड़ा। निर्वासित तिब्बती प्रशासन ने स्थानीय भारती प्रशासन के अधिकारियों, स्थानीय भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों और मीडिया के लिए एक रात्रिभोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस भोज कार्यक्रम की अध्यक्ष कार्यवाहक सिक्योंग श्री पेमा छिनजोर ने की। ◆

जिनपिंग के पहले 100 दिनः मानवाधिकारों पर प्रगति का अभी भी है इंतजार

(माया वांग, ग्लोबल पोस्ट, 9 जुलाई, 2013)

वादों के मुताबिक जो लोग सुधारों के लिए दबाव डाल रहे हैं उनको सजा मिलना जारी है। उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार लूट–खसोट, वृद्धि दर का सुस्त होना, जापान के साथ तनाव, सन्नीलैंड्स में अमेरिकी समिटः चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल के पहले सौ दिन फीके नहीं रहे हैं। लेकिन इनसे क्या किसी तरह का संकेत मिलता है कि उनका कार्यकाल उनके पूर्ववर्तियों से अलग होगा? उनके 14 मार्च को राष्ट्रपति का पद औपचारिक रूप से ग्रहण करने से पहले बहुत से लोगों को यह उम्मीद थी कि शी जिनपिंग और नया नेतृत्व उन क्षेत्रों के लिए कुछ ऐसे साहसी कदम उठाएगा जिनमें लंबे समय से नीतिगत पक्षघात की स्थिति बनी हुई है, खासकर मानवाधिकार और राजनीतिक सुधारों के मामले में। शी के शुरुआती भाषणों से इन उम्मीदों को मजबूती मिलती थीः उन्होंने खुद को एक सुधारक की तरह पेश किया था, एक ज्यादा जवाबदेह सरकार का वायदा किया, अधिकारियों द्वारा संपदा के खुले प्रदर्शन को रोकने का आदेश दिया और भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज कराए।

शी सरकार ने कई कुख्यात सरकारी व्यवस्थाओं में बदलाव के भी संकेत दिए थे जिनमें 'हुकोउ' आवासीय पंजीकरण (जिसमें ग्रामीण प्रवासियों के साथ भेदभाव किया जाता है), याचिका प्रणाली और 'मजदूरी के द्वारा पुनर्शिक्षा' (आरटीएल) व्यवस्था शामिल है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को चार साल तक बिना किसी मुकदमे के एक तरह से कैद में रखा जा सकता है। आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख की ताकत कम करने से भी यह उम्मीद बनी है कि "स्थिरता बनाए रखने" की लगातार फूलती मशीनरी जिससे असंतुष्टों का दमन सुनिश्चित होता था, उस पर आखिरकार अंकुश लगाया जाएगा।

लेकिन संभवतः यह उम्मीद कर लेना अयाथार्थवादी था कि लंबे समय से चीन सरकार द्वारा जारी चलन को वह 100 दिन के भीतर ही बदलकर रख देंगे। लेकिन यह उम्मीद करना अतार्किक नहीं होगा कि नया नेतृत्व बुनियादी सुधारों को लेकर गंभीर है और वह उन लोगों को सजा देना बंद करेगी जो सरकार से उसके वायदों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं।

शी के राष्ट्रपति बनने के दो हफ्तों के बाद ही 31 मार्च को बीजिंग के जनता चौक पर चार लोग एक बैनर लहराने के लिए हिरासत में ले लिए गए। इस बैनर पर सरकार से यह मांग की गई थी कि वह अधिकारियों के संपत्ति को सार्वजनिक करने की नीति लाए।

इसके बाद से पुलिस ने 11 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है जो कथित रूप से इसी तरह के अभियान में शामिल थे। चीन के राजनीतिक एवं कानूनी समिति के प्रमुख द्वारा इस साल के अंत तक 'आरटीएल के इस्तेमाल को रोकने' के वयादे के कुछ महीनों बाद ही जून की शुरुआत में बीजिंग के फिल्मकार दु बिन को "अशांति पैदा करने" के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बिन ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी जिसमें आरटीएल केंद्र में भारी प्रताड़ना को दर्शाया गया था। शी ने मार्च में कहा था, "हमेशा जनता की आवाज सुनो" लेकिन चीन सरकार ने अभिव्यक्ति या सभा करने की स्वतंत्रता पर नियंत्रण को कम नहीं किया है।

मई महीने में पार्टी–सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को एक निर्देश जारी किया कि वे मानवाधिकार जैसे "सार्वभौमिक मूल्य" सहित सात वर्जित विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। इसी तरह एक दूसरे आदेश में इन संस्थाओं से यह आह्वान किया गया कि युवा लेक्चरर के बीच "विचारधारा की शिक्षा" को मजबूत करें। जून की शुरुआत मे सरकार ने टिनामेन नरसंहार की 24वीं वर्षगांठ मनाने के आवेदन को नामंजूर कर दिया और ऐसा अनुरोध करने वाले लोगों को प्रताड़ित किया गया। ऐसा आवेदन करने के बाद जियांगसू के एक कार्यकर्ता गु यिमिन को जून में "विध्वंस को बढ़ावा देने" के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ज्यादा दुःखदायी बात यह है कि ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की गई और हिंसा का सहारा लिया गया, जबकि राष्ट्रपति शी ने "संविधान और कानून का शासन बनाए रखने की बात कही थी। मई महीने में वकीलों के एक समूह ने सिचुआन प्रांत के एक गैरकानूनी 'ब्लैक जेल' का दौरा करने की कोशिश की तो कुछ लोगों द्वारा उनकी पिटाई की गई। पुलिस न केवल उनकी रक्षा करने में विफल रही, बल्कि उसने "सरकारी कामकाज में बाधा डालने" के आरोप में वकीलों को हिरासत में भी ले लिया। अप्रैल माह में जब वकील छेंग हाई ने फालुन गोंग के अपने मुवक्किलों के मुकदमे में अचानक देरी होने के बारे में दालियान कोर्ट में पूछताछ की तो उन्हें कोई जवाब तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस अधिकारियों द्वारा पिटाई जरूर की गई। आंदोलनकारी लोगों को दंड देने के लिए उनके परिवार वालों को परेशान करना कानून के शासन की भावना के पूरी तरह से खिलाफ है, जैसा कि जून में लिउ हुई को 11 साल के कठोर कारावास की सजा से देखा जा सकता है। हुई फिलहाल जेल में बंद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लिउ जियाओबो के रिश्तेदार हैं। इसी तरह निर्वासित आंदोलनकारी छेन गुआंगछेंग के परिवार जनों को भी लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है।

शी सरकार के लिए सार्थक बदलाव शुरू करने में अब भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। लेकिन यदि और 100 दिन बीत जाने पर भी मुकदमे का सामना करने वाले आंदोलनकारियों और उनके परिवार जनों की सूची बढ़ती गई तो शी के शब्द आडंबर पर कोई भरोसा नहीं करेगा। चीनी जनता अब भी असल प्रगति का इंतजार कर रही है और राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार लाने में नाकामी से गंभारी "नागरिक अशांति" पैदा हो सकती है जिसकी शी ने चेतावनी दी थी। ◆

(माया वांग हांगकांग स्थित ह्यूमन राइट्स वाच में एशिया रिसर्चर हैं)

आगे के लिए एक नया रास्ता

तिब्बत में अलग रवैया अपनाने का प्रस्ताव यह साबित करता है कि चीन में कुछ लोग यह जानते हैं कि उनकी नीतियां कारगर नहीं हैं

(दि इकनॉमिस्ट, 22 जून, 2013)

चीनी अधिकारियों में तिब्बत पर एक रूढ़िवादी समझ यह है कि मौजूदा दलाई लामा के निधन के बाद तिब्बत की समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। तिब्बत के पर्वतीय इलाके पर चीन का सख्त नियंत्रण है और उसका मानना है कि सारे पत्ते उसके पास हैं। वह दलाई लामा के पुनर्जन्म का चयन कर सकता है और सब कुछ उसके मुताबिक ही होगा।

इसलिए तिब्बत पर नजर रखने वाले लोगों को इस महीने हांगकांग की एक पत्रिका में तिब्बत मामले की एक प्रसिद्ध चीनी विद्वान का इंटरव्यू देखकर आश्चर्य और खुशी हुई। इस इंटरव्यू में लगभग एक पीढ़ी में पहली बार सरकार के किसी वरिष्ठ सलाहकार ने यह सुझाया है कि तिब्बत में आर्थिक विकास के साथ लगातार जारी राजनीतिक दमन की चीनी नीति कारगर नहीं है और इसे बदलने की जरूरत है।

जिन वेई नाम की यह अधिकारी तिब्बतियों को प्रेम करने वाली कोई नरमदिल महिला नहीं हैं। वह बीजिंग के एक थिंकटैंक केंद्रीय पार्टी स्कूल में नस्लीय और धार्मिक अध्ययन मामले की निदेशक हैं। वह भी चीन में मान्य इस पक्ष का समर्थन करती हैं कि तिब्बत, चीन का अभिन्न हिस्सा है (जैसा कि चीन के ज्यादातर लोग मानते हैं)। लेकिन उन्होंने सुझाया है कि कम्युनिस्ट पार्टी इस इलाके में हर सांस्कृतिक और धार्मिक समस्या से जिस तरीके से निपट रही है वह विनाशकारी है और उससे चीजें और बिगड़ रही हैं। उनका कहना है कि संस्कृति और धर्म के कुछ टक. राव टाले नहीं जा सकते लेकिन उनको संभाला जा सकता है और उन्हें राज्य के लिए खतरे की तरह नहीं देखना चाहिए। सुश्री जिन ने कहा कि दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ बाधित वार्ता फिर से शुरू की जानी चाहिए उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि दलाई लामा को हांगकांग या मकाऊ में बुलाया जाए। उनका सबसे विवादास्पद सुझाव यह है कि चीन को उनके अगले पुनर्जन्म के बारे में बात करनी चाहिए और आगे चलकर उन्हें खुद तिब्बत में आने देना चाहिए। चीनी शासन जिस तरह से चलता है उससे यह लगता है कि सुश्री जिन को इस तरह के विचार रखने की इजाजत शीर्ष स्तर के नेतृत्व से मिली है। यह शायद हाल में नेतृत्व में हुए बदलाव से आया है। असल में 1980 के दशक के अंत में तिब्बत में कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव हू जिनताओ ही थे, जिन्हें ल्हासा में 1988 के दंगों के बाद यह जिम्मेदारी मिली थी। बाद में वह पार्टी के मुखिया और राष्ट्रपति बने और उन्होंने उसके बाद जो कठोर नीतियां अपनाईं वह तब से ही तिब्बत पर हावी रहीं। पिछले साल नवंबर में उन्होंने पार्टी के नेता का और इस साल मार्च में राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया। यह सुश्री जिन की तरह से एक संकेत हो सकता है। उनके बयान से यह भी ध्वनित हो रहा है कि तिब्बत नीति श्री हू समर्थकों के हाथ में अब नहीं होनी चाहिए।

nykbl ykek ij fgpfdpkgV

इस प्रस्ताव का कट्टरपंथी भारी

विरोध करेंगे, जो ऐसी किसी भी तरह की नरमी नहीं देखना चाहते जिससे तिब्बत की आज़ादी का रास्ता प्रशस्त हो। इसलिए पश्चिम को फूंक–फूंक कर कदम रखना चाहिए। इन विचारों के प्रति अति उत्साही समर्थन से चीनी नेतृत्व के बीच व्यापक तौर पर फैली यह धारणा और मजबूत होगी कि दलाई लामा पश्चिम के साथ मिलकर चीन को बांटने का षडयंत्र कर रहे हैं। जबकि तथ्य यह है कि वह लंबे समय से यह कहते रहे हैं वह आज़ादी की मांग नहीं कर रहे और तिब्बत के लिए केवल स्वायत्तता चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर चीनी अफसरशाही उनके विचारों को काफी संदेह के साथ देखती है।

इस प्रकार दलाई लामा के साथ तालमेल बनाना चीन सरकार के लिए एकमात्र उम्मीद है जिनके जरिए वह ऐसे किसी समझौते पर पहुंच सकती है जो सभी तिब्बतियों को स्वीकार्य हो। इस हफ्ते एक और तिब्बती ने खुद को आग के हवाले कर मौत को गले लगा लिया है (वर्ष 2011 से अब तक 119 आत्मदाह) और निचले स्तर तक नियंत्रण का जो नया स्वरूप दिख रहा है उससे कहीं से यह संकेत नहीं मिलते कि तिब्बत पर आसानी से शासन चलाया जा सकेगा। मौजूदा दलाई लामा का निधन तिब्बत में असल समस्याओं की एक शुरुआत हो सकती है, अंत नहीं। निर्वासित नेता की व्यक्तिगत हस्ती का कोई दबाव और अहिंसा पर चलने की नीति पर उनके जोर के न रहने के बाद युवा तिब्बती आक्रामक रुख अख्तियार कर सकते हैं।

चीन और तिब्बत दोनों के हित के लिए यह उम्मीद की जानी चाहिए कि सुश्री जिन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिले। यह विचार तो अजीब लगता है कि एक कम्युनिस्ट सरकार एक पवित्र भिक्षु के साथ बैठकर उनके पुनर्जन्म पर चर्चा करेगी। लेकिन सुश्री जिन के प्रस्ताव वास्तव में अब तक तिब्बत के बारे में अपनाए जा रहे उन कट्टर वैचारिक रवैए से तो ज्यादा व्यावहारिक लगते हैं जिनसे केवल वे लोग अलग–थलग ही हुए हैं जिनको चीन अपना बताता है। ◆

ड्रैगन का स्टील जैसा शिकंजा

हाल के कुछ घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि चीन तिब्बत और दलाई लामा पर अपनी नीतियों की समीक्षा कर रहा है। लेकिन जयदेव रानाडे कहते हैं कि इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

(हिंदुस्तान टाइम्स, 30 जून, 2013)

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद बीजिंग ने तिब्बत पर अपना ध्यान बढ़ा दिया है और यह इस तथ्य की वजह से है कि देश में रहने वाले तिब्बतियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। निर्वासित तिब्बती समुदाय के कुछ वर्गों को लगता है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनके और दलाई लामा के प्रति 'नरम' नीति अपना सकते हैं, लेकिन इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है।

इसके विपरीत स्थिति तो यह है कि निष्ठा और राजनीतिक विश्वसनीयता पर पार्टी के फिर से जोर देने से पार्टी में तिब्बतियों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ेगा। वर्ष 2011 में तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र (टीएआर) के पार्टी सचिव छेन गुआंगवो ने इस बात की पुष्टि की थी कि संसाधन बहुल तिब्बत को केंद्र के नियंत्रण में बनाए रखा जाएगा।

उन्होंने यह खुलासा किया था कि समूचे तिब्बत में निगरानी बढ़ा दी गई है, भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों को वित्तीय प्रलोभन दिया जा रहा है और मठों में ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे उन्हें समाजवादी सामाजिक व्यवस्था को अपनाने में मदद मिले।

सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है और सभी प्रशासनिक स्तर पर राजनीतिक अधिकार को मजबूत किया गया है और इसके लिए हर साल हर गांव में नए–नए पार्टी सदस्य जोड़े जाते हैं। इन उपायों के बावजूद टीएआर और तिब्बती इलाकों में आत्मदाहों की संख्या बढ़ती जा रही है जिससे यह पता चलता है कि चीन के भीतर रहने वाले तिब्बतियों में असंतोष है। इससे चीनी नेतृत्व भ्रमित हो गया है। वांग लिक्सियांग द्वारा आत्मदाहों का विश्लेषण इसकी वजह बताता है। इसमें बताया गया है कि "साहस और लचीलापन" और "दलाई लामा के लिए प्रार्थना" इसके पीछे मुख्य प्रेरक कारक हैं। इसमें यह रेखांकित किया गया है कि विरोध आंदोलन का केंद्र अब तिब्बत की ओर चला गया है और चीन के भीतर रहने वाले तिब्बती इसे अपने संघर्ष की तरह चला रहे हैं।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यह समझती है कि चीन के भीतर अशांति बढ़ सकती है और उसे यह आशंका भी है कि तिब्बतियों के विरोध प्रदर्शन की यह भावना बाकी 60 लाख तिब्बतियों तक भी पहुंच सकती है। इसके बाद यह आसानी से बहुसंख्यक हान जनसंख्या तक पहुंच सकती है, इसके बावजूद कि अन्य मौजूदा असंतोष की वजह से उनके और तिब्बतियों के बीच दूरी बनी हुई है। इसका एक उदाहरण है अब इजरायल में रहने वाली हान चीनी कवि और फिल्मकार तांग डैनहोंग का एक निबंध जो इस साल जनवरी में चीनी वेबसाइट्स पर खूब प्रचारित हुआ। उनके निबंध में टीएआर में रहने वाले तिब्बतियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले असंतोष को व्यक्त किया गया था। तनाव को दूर करने के लिए बीजिंग ने ऐसे प्रयास किए हैं कि इस हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले तिब्बती बौद्धों पर प्रभाव कायम हो। इसके लिए उन्हें भौतिक प्रोत्साहन दिया जाता है, दलाई लामा के प्रभाव को कम करने की कोशिश की जाती है और तिब्बती समुदाय के बीच फूट डालने की कोशिश की है। हाल की दो घटनाओं से पता चलता है कि चीन संभवतः तिब्बत और दलाई लामा पर

t;nso jkukMs Hkkjr ljdkj ds dSfcusV lfpoky; esa iwoZ vfrfjDr lfpo vkSj jk"Vªh; lqj{kk ijke'kZ cksMZ ds lnL; gSaA

अपनी नीति की समीक्षा कर रहा है। गत 3 जून को हांगकांग तिब्बती और हान चीनी मैत्री संगठन ने दलाई लामा को शहर में आने का निमंत्रण दिया। इस संगठन के चीन समर्थक होने का संदेह है और इसके अध्यक्ष हांगकांग नॉर्थ वेस्ट एक्सप्रेस शिपिंग कंपनी के दिवालिया हो चुके पूर्व प्रमुख फिलीप ली कोइहोप हैं। ली फिल. हाल एक मरीन इंस्पेक्टर हैं। दूसरा संकेत मिलता है, हांगकांग के एशिया वीकली में गत 6 जून को छपे सीसीपी सेंट्रल पार्टी स्कूल की जिन वेई के इंटरव्यू से। पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सीधे नियंत्रण में काम करने वाला केंद्रीय पार्टी स्कूल एक ऐसा संगठन है जहां पार्टी के नए उभरते कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और जो लोग इसमें प्रशिक्षण हासिल करते हैं अक्सर उनके "राजनी. तिक विश्वसनीयता" की परीक्षा ली जाती है। अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के मसले पर पकड़ रखने वाली जिन वी इस बात का महत्वपूर्ण खुलासा करती हैं कि तिब्बत मसले और दलाई लामा पर चीनी नेतृत्व की सोच क्या है। उनका सुझाव है कि सीसीपी और दलाई लामा के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत फिर से शुरू की जानी चाहिए–जो कि वर्ष 2010 से ही बाधित है– और उन्होंने आरोप लगाया कि तिब्बत में असंतोष के लिए टीएआर के कई पार्टी सचिवों द्वारा किया जाने वाला धार्मिक भ.`दभाव मुख्य वजह है। उनका सुझाव है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, लेकिन "दलाई गुट" के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के मतभेद को "प्रतिरोध और परस्पर विरोधी" बताकर उन्होंने एक तरह से तिब्बत पर बीजिंग के सख्त रवैए को बनाए रखने की ही वकालत की है। उन्होंने वार्ता शुरू करने को इस आधार पर न्योयोचित बताया है कि दलाई लामा 60 लाख तिब्बतियों के लिए "जीवित ईश्वर" जैसे माने जाते हैं और चीन उनसे "दुश्मन की तरह व्यवहार नहीं कर सकता।" इस बात पर जोर देते हुए कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दलाई लामा का पुनर्जन्म चीन में हो, उन्होंने चेतावनी दी कि यह पाने में अगर हम विफल रहे तो इसका "तिब्बती इलाके में स्थिरता और सुरक्षा पर गहरा असर पड़ेगा।" उन्होंने सुझाव दिया है कि पहले आसान मसलों को सुलझाना चाहिए और 'मध्य मार्ग नीति' और अन्य मसलों को फिलहाल परे रख देना चाहिए। बाद में दलाई लामा को हांगकांग, मकाऊ या तिब्बत भी आने दिया जा सकता है। दलाई लामा के प्रति तिब्बतियों की भावना पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने यह खुलासा किया कि लोगों ने उनसे यह कहा है कि, "इस जीवन में मैं कम्युनिस्ट पार्टी पर निर्भर हूं, अगले जन्म में मैं दलाई लामा पर निर्भर रहूंगा!"

उन्होंने दलाई लामा की पूजा को बिना किसी राजनीतिक महत्व का बताया और उनके अनुसार "तिब्बत की स्वाधीनता" एक बेकार शब्द है। उनके इंटरव्यू से शायद पहली बार यह पता चल पाया है कि कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व आत्मदाह की घटनाओं के बारे में क्या सोचता है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि इनसे चीनियों और तिब्बतियों के बीच एक नस्लीय टकराव को बढ़ावा मिला है।

जिन वेई के इंटरव्यू से यह पता चलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी नीतियों में कुछ लचीलापन ला सकता है जिसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म चीन के भीतर हो। दूसरी तरफ शी जिनपिंग ने तिब्बत सहित अन्य सभी मसलों पर बातचीत के लिए पैरामीटर परिभाषित कर दिए हैं, जनवरी में यह घोषित कर कि, "कोई भी दूसरा देश कभी यह उम्मीद न पाले कि हम अपने मुख्य राष्ट्रीय हितों पर कोई मोलतोल करेंगे और न ही उन्हें यह उम्मीद पालनी चाहिए कि अपने देश की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों पर किसी तरह की आंच बर्दाश्त करेंगे।"

(जयदेव रानाडे भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में पूर्व अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्श बोर्ड के सदस्य हैं) ◆

‘कुछ भी हो लेकिन मानवीय नहीं‘

तिब्बतियों ने चीन को अंदर से बेपर्दा किया

(स्पीगेल ऑनलाइन इंटरनेशनल, 16 जुलाई) एंड्रियाज लॉरेंज

dE;fuLV ikVh d ,d mPPk Lrj d vf/kdkjh u ,d fdrkc fy[kh g ftlesa frCcfr;ka d ifr phu }kjk fd, tk jg vijk/kk dk mtkxj fd;k x;k gA mud ikVh lg;kfx;ka dk vc Hkh ;g ugh yxrk fd mUgkau ikVh d i{k ij dkbZ /kCck yxk;k gA

,d frCcrh tk dHkh phuh dE;fuLV ikVh dk leFkd Fkk vkj ftlu chftx d C;jkØlh e viuk dfj;j ik;k Fkk] vc mlu viu n'k e phuh uhfr ij ,d vkykpukRed fjikV idkf'kr dju dk fu.k; fy;k gA n'k Hkj e i[;kr bl vf/kdkjh u viuh igpku Nqiku d fy, bl vf/kdkjh u phu d ,d ikrh; 'kgj e ,d jLVkjV e Lihxy l xkiuh; rjhd l eykdkr dhA mudk mEehn g fd mUgkau viu ykxk d neu d ckj e tk dN fy[kk g ml if'pe e ,d fdrkc e Nkik tk,xk rkfd phu d urkvk ij dN ncko cuA

दोर्जी रिनछेन 23 अक्टूबर, 2012 को भोर में ही जग गए थे जो कि उनके जीवन का अंतिम दिन था। 58 वर्षीय रिनछेन ने लाबरांग मठ जाकर बौद्ध प्रार्थना चक्र घुमाए, उसके बाद अपनी झोपड़ी में लौट आए, उसकी सफाई की और फिर मठ चले गए।

चीन के गांसू प्रांत के एक कस्बे शियाहे के मुख्य चौराहे पर स्थित पुलिस थाने के पास जाकर इस तिब्बती किसान ने अपने शरीर को पेट्रोल से भिगोया और आग लगा लिया। मोबाइल फोन से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि आग की लिपटों में घिर चुके रिनछेन तब तक चौराहे पर दौड़ते रहे, जब तक जमीन पर गिर नहीं पड़े। पुलिस और सैनिक तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए, उन्होंने आसपास जमा लोगों से धक्का–मुक्की की जो दोर्जी के शव को उनके घर ले जाकर तिब्बती परंपरा से उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। आखिकार अधिकारियों को नरम होना पड़ा।

दोर्जी तिब्बत में चीनी शासन के विरोध में मार्च 2011 से अब तक आत्मदाह करने वाले 100 से ज्यादा तिब्बतियों में से एक हैं। इसके कुछ दिनों बाद ही अपना जीवन होम कर देने वाले एक अन्य व्यक्ति ने एक पत्र लिख छोड़ा था जिसमें इन अभागे लोगों की भावना को अभिव्यक्त किया गया हैः “तिब्बत में कोई आज़ादी नहीं है। परमपावन दलाई लामा को अपने घर वापस लौटने की इजाजत नहीं दी जा रही। पंचेन लामा जेल में हैं।”

“दुनिया की छत” कहे जाने वाले इस इलाके के लोगों में हताशा है। इसके पहले कभी भी इतने ज्यादा तिब्बतियों ने अपनी नियति पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह से अपने जीवन का बलिदान नहीं किया था। हालांकि, हर कोई यह नहीं मानता कि यह सही तरीका है। लाबरांग मठ से कुछ सौ किलोमीटर की दूरी पर बैठे कम्युनिस्ट पार्टी के एक उच्च्य अधिकारी इस पर असहमति में अपना सिर हिलाते हैं। उनका कहना है कि, “आत्मदाह एक अतिशय प्रतिक्रिया, एक जरूरत से ज्यादा क्रांतिकारी कार्रवाई है। बौद्ध धर्म में आत्महत्या वर्जित है।” हालांकि, उनका कहना है कि वह इसके पीछे की सोच को समझते हैं।

उनके मातृभूमि तिब्बत में घटनाएं नाटकीय मोड़ ले रही हैं। उन्होंने कहा, “तिब्बत में आ. र्थिक स्थिति, लोगों के रहन–सहन के स्तर, संस्कृति और शिक्षा में काफी सुधार हुआ है। लेकिन सरकार इस विकास के बदले तिब्बतियों से बहुत ऊंची कीमत वसूल रही है। सरकार उन्हें हिंसा के सहारे अनुशासित बनाने की कोशिश कर रही है। वहां बहुत ज्यादा निगरानी और सीमित आज़ादी है।”

यह व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। वे न केवल तिब्बत बल्कि पूरे चीन में प्रख्यात हैं और कोई भी यह संदेह नहीं कर सकता कि वह सरकार का विरोध करेंगे। वह उन लोगों में शामिल रहे हैं जो लंबे समय से इसमें भरोसा करते रहे हैं कि एक समाजवादी चीन बनाने का लक्ष्य पूरा होगा जिसमें न केवल हान चीनी, बल्कि तिब्बती और अन्य सभी नस्लीय समूह के लोग भी बेहतर जीवन जी पाएंगे। लेकिन अब वह अपना एक नजरिया कायम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “मैं एक तिब्बती हूं और मैं सरकार में काम करता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि कि वास्तव में क्या हो रहा है।”

ßif'pe d vueku l Hkh T;knk [kjkc g fLFkfrÞ

वह युवा अवस्था से ही चीन सरकार की सेवा में हैं। बहुत से तिब्बतियों की तरह, जिन्हें यह तथ्य पता है कि चीन उनके देश पर तब से ही शासन कर रहा है, जब 1950 में चीनी सेनाओं ने उस पर चढ़ाई की थी। इनमें पार्टी के पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी, प्रोपेगंडा करने वाले, पत्रकार और इंजीनियर शामिल हैं जो कि विदेशी शासन में भी शांति से रहना चाहते हैं। वे सरकार के अनुकूल काम करते हैं, पार्टी के नारों को प्रचारित करते हैं और अपनी बढ़ती संपन्नता का मजा लेते हैं, हालांकि अक्सर अंत में वे खुद को दीन–हीन ही महसूस करते हैं। इससे यह समझने में आसानी होती है कि आखिर क्यों इस सामयिक गवाह ने बैठकर तिब्बत के हालिया इतिहास का अपनी आंखों से देखा हुआ लेखा–जोखा कलमबद्ध करने का निर्णय लिया। उनका ध्यान उस बात पर है जिन्हें सरकारी प्रोपेगंडा करने वाले या इतिहासकार दबाने की कोशिश करते हैं या चमकीले रैपर में पेश करते हैं। वह लिखते हैंः “हर चीज पहले भी और अब भी उससे बदतर रही है जितना पश्चिम में बैठे लोग शक करते हैं।”

उन्होंने यह निश्चय किया है कि जब तक संभव होगा सामने नहीं आएंगे। वह कहते हैं, “मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम सामने आए, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पेश का उल्लेख करें, आप सामान्य पदों में केवल मेरे रहने के

स्थान का जिक्र कर सकते हैं।"

उनका उद्देश्य है कि यह किताब विदेश में छपे, जो कि निश्चित रूप से उनके पास एकमात्र विकल्प है। यदि यह बात सामने आ गई एक सम्मानित अधिकारी वास्तव में एक तिब्बती विद्रोही है जो "तिब्बतियों के नियति" की तुलना नाजियों के शासन के तहत रहने वाले यहूदियों से करता है तो उनका सुविधाजनक अस्तित्व तत्काल खत्म हो सकता है। उन्हें जेल भेजा जा सकता है और शायद मौत की सजा भी दी जा सकती है।

यह किताब मंदारिन भाषा में लिखी गई है जो बीजिंग के सत्तारूढ़ वर्ग की भाषा है। लेखक यह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके लोगों को समझें जो उनके मुताबिक एक विदेशी यूटोपिया के बदले "रक्त के भंवर और पापमुक्ति की आग के बीच फंसे हुए हैं।"

विडंबना यह है कि शुरुआत में कुछ तिब्बती तिब्बत पर चीनी आक्रमण से खुश थे क्योंकि उनके नए शासकों ने आधुनिकता और समृद्धि लाने का वादा किया था। उनको लगता था कि माओत्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट उनको सामंतवादी व्यवस्था से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन जब माओ के नेतृत्व वाले चीन सरकार ने तिब्बतियों को उनके धर्म और परंपरा को बनाए रखने की आज़ादी देने का वायदे पर कायम नहीं रह पाई तो माहौल पूरी तरह बदल गया। खेती का सामूहीकरण वास्तव में इस इलाके के लिए विनाशकारी साबित हुआ। तिब्बती नोमैड को तथाकथित कम्यूंस में रहने को बाध्य किया गया जिनसे उनकी परंपरागत जीवन शैली बर्बाद हो गई। इस प्रकार 1950 के दशक से ही वहां अशांति बढ़ने लगी।

vR;kpkj vkj cc]j uhfr;k

महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति (1966 से 1976) के दौर में रेड गार्ड्स (जिनमें कई तिब्बती भी थे) अपने "संशोधनवादी" और "साम्राज्यवादी" देशवासियों पर हमले किए। हजारों भिक्षुओं को पीट–पीट कर मार डाला गया या शिविरों में डाल दिया गया और प्र. ाचीन स्मारकों को नष्ट कर दिया गया। रेड गॉर्ड ने अपने तोपखाने का इस्तेमाल सैकड़ों मठों को जमींदोज करने के लिए किया।

कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी उनके विषयों की संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे। उदाहरण के लिए तिब्बती महिलाओं को उसी तरह के ट्राउजर पहनने को बाध्य किया गया जैसा कि हान चीनी महिलाएं पहनती थीं और उनसे अपनी चोटी काटने को कहा गया। कुलों के बुजुर्गों और मठ अध्यक्षों को पुनर्शिक्षा शिविर में भेजा गया, जहां उन्हें हर दिन माओ के सिद्धांत पढ़ने को बाध्य किया जाता था। चीनी सैनिकों ने किसी भी तरह के विद्रोह को बर्बरतापूर्वक दबाया। जब भिक्षुओं ने 1956 में जनमुक्ति सेना के एक अफसर की हत्या कर दी तो चीनी घुड़सवार सेना के एक रेजीमेंट ने इसका बदला गांसू प्रांत के किउजी नावा कस्बे में लिया जहां उन्होंने "करीब 200 निर्दोष महिलाओं और बच्चों पर हमला कर दिया। उन्होंने एक टेंट को घेर लिया, उसके भीतर सैकड़ों ग्रेनेड फेंके और उसके बाद उसमें आग लगा दिया।"

लेखक ने इसी तरह का नरसंहार देखने वाले एक पूर्व सैनिक का बयान भी दिया है जो कह रहा है, "कई महिलाओं के गुप्तांग में तलवार घोंप दिया गया और उनके स्तन के टुकड़े–टुकड़े कर दिए गए। दो–तीन साल की उम्र के बच्चों को पकड़ा गया और उन्हें येलो नदी में फेंक दिया गया।" 1980 के दशक के शुरुआत में ही कम्युनिस्ट पार्टी को यह स्वीकार कर लेना चाहिए था कि उसने अपनी बर्बर नीतियों की वजह से "लोगों के हितों को गंभीरता से नुकसान पहुंचाया है।" तब से ही तिब्बत एक स्थायी तौर पर अशांत इलाका बना हुआ है। जैसा कि कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी लिखते हैं, चीन का यह दावा है कि "पार्टी नेतृत्व के तहत लाखों तिब्बती किसानों को अपने घरों का मालिक बना दिया गया" वास्तव में प्रोपेगंडा से ज्यादा कुछ नहीं है।

उनके विचार से अशांति और तिब्बतियों के गुस्से की कई वजहें हैं। उनकी लंबे समय से संजोया हुआ यह सपना धूमिल हो रहा है कि दलाई लामा एक दिन भारत से लौटेंगे, जहां निर्वासित तिब्बती सरकार का मुख्यालय है। चीन उनकी एक "देशद्रोही" कहकर आलोचना करता रहा है और उनसे बातचीत करने से भी इनकार करता है। यह चीन के लिए लज्जाजनक स्थिति थी जब 1987 में दलाई लामा ने वाशिंगटन में अमे. रिकी कांग्रेस के सदस्यों को संबोधित किया और उन्होंने अपनी पांच सूत्रीय शांति योजना पेश की। उन्होंने यह मांग की कि तिब्बत में चीन हान चीनियों को बसाना बंद करे और तिब्बत पठार को नाभिकीय कचरा निपटाने के स्थान के रूप में इस्तेमाल करना बंद करे।

कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के मुताबिक दलाई लामा के इस दौरे के बाद "युवा बुद्धिजीवियों, कुछ अधिकारियों, मजदूरों, किसानों और चरवाहों में विरोध की भावना नए सिरे से बढ़ने लगी।"

lk{; fjikVZ dk nLrko

इसके बाद वर्ष 1988 में चीन ने एक और गलती की। वार्षिक महान प्रार्थना समारोह के दौरान वरिष्ठ अधिकारी विशाल समारोह को देखने के लिए तिब्बत की राजधानी ल्हासा में स्थित जोखांग मंदिर की छत पर जमा हो गए। वे सीधे उस कमरे के ऊपर खड़े थे जिसे भिक्षु पवित्र मानते थे। समारोह के दौरान अक्सर दलाई लामा इसी कमरे में विश्राम करते थे।

जल्दी ही अधिकारियों के ऊपर पत्थरों की बरसात होने लगी। भीड़ ने रास्ते में खड़े सैनिकों की पिटाई की और तिब्बत के उप पार्टी प्रमुख सहित कई पार्टी अधिकारियों को खिड़की से रस्सी के सहारे लटककर भागना पड़ा। इसके फलस्वरूप अगले हफ्तों में भिक्षु और भिक्षुणी सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे, जब तक बीजिंग ने आखिरकार दमन नहीं शुरू किया। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ तिब्बती कम्युनिस्ट अधिकारियों को हटा दिया और उनकी जगह हान चीनी नस्ल के लोगों को बिठाया, इनमें हू जिनताओ भी थे जो कि बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और चीन के राष्ट्रपति बने। एक साल बाद ही हू ने विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ तिब्बतियों पर सैनिकों को खुलेआम गोलीबारी की इजाजत दे दी। लेखक के मुताबिक इस घटना में 138 लोग मारे गए, 3,870 गिरफ्तारियां हुईं, जबकि बहुत से लोगों का अपहरण कर लिया गया।

लेखक ने कई गवाहों के बयान दिए हैं, जिनमें से एक कहता हैः "उन्होंने पूरे ल्हासा के लोगों की छानबीन की और जिनको पसंद नहीं करते थे उन्हें गिरफ्तार किया। पहले लोगों की पिटाई की गई और इसके बाद गिरफ्तार लोगों को पुलिस की कोठरियों में ठूंस दिया गया।" लेकिन ये कोठरियां इस तरह से भरी हुई थीं कि कई गिरफ्तार लोग घुटन से मर गए। गवाह ने बताया, "जब कुछ लोग मर गए तो उनके लिए इसका इससे ज्यादा महत्व नहीं था जैसे कोई व्यक्ति घास पर चल रहा हो और उसके पैरों से नीचे दबकर कोई चींटी मर जाए।"

तिब्बतियों के असंतोष की एक वजह यह भी है कि चीन के दूसरे हिस्सों के चीनी प्रवासी तिब्बत में ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल कर खेती कर रहे हैं। लेखक की राय में इससे गंभीर पर्यावरणीय नुकसान होता है क्योंकि धीरे–धीरे जमीन मरुस्थल में बदलता जाता है। उन्होंने कहा, "तिब्बतियों के पास रहने के लिए कम से कम जगह मिल रही है और वातावरण ज्यादा से ज्यादा ठंडा और विकट हो रहा है।"

अधिकारी बताते हैं कि चीन की लाप. रवाह पर्यावरण नीति का एक साफ उदाहरण क्विंघई झील है। बहुत ज्यादा चारागाह वाली जमीन पर खेती होते जाने और बहुत ज्यादा नहर प्रणाली विकसित होने की वजह से झील में जाकर मिलने वाली 108 नदियों में से आज आठ ही बची रह गई हैं।

lMdksa ij ruko

वर्ष 1989 तक चली अशांति के बाद चीजें कुछ साल तक सामान्य रहीं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हू ने अरबों डॉलर के निवेश से तिब्बतियों को लुभाने का प्रयास किया। इस इलाके में मिले अपार खनिज संसाधन और चीन एवं उसके आर्थिक रूप से प्रतिद्वंद्वी देश भारत के बीच एक बफर क्षेत्र होने के नाते इसके सामरिक महत्व को देखते हुए तिब्बत असल में चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज ल्हासा की सड़कों पर हर जगह तनाव है क्योंकि वहां चीनी सुरक्षा बलों की भरमार है जो कब्जा जमाने वाले मालिकों की तरह व्यवहार करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर के व्यक्ति यह लेखक लिखते हैं, "सशस्त्र पुलिस के जवान जिस तरह से व्यवहार करते हैं वह किसी भी तरह से मानवीय नहीं कहा जा सकता। वे लोगों की इतनी निर्ममता से हत्या करते हैं जैसे कि जहरीले सांप को मारा जाता है। वे स्थानीय निवासियों की अंधाधुंध तरीके से पिटाई करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी लूट लेते हैं और जो लोग इसे बचाने की कोशिश करते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है।"

मार्च, 2008 में जब बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तैयारी कर रहा था तो ल्हासा के निवासियों ने एक बार फिर से विद्रोह किया। लेकिन इस बार विरोध प्रदर्शन करने वाले भिक्षुओं के साथ सभी इलाकों के तिब्बती और स्कूली विद्यार्थी, ऑफिस के कर्मचारी भी शामिल हुए। पुलिस और सेना ने करीब 6,000 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के पास अब तिब्बतियों को संतुष्ट करने का बस एक रास्ता दिख रहा थाः ज्यादा से ज्यादा निवेश करो और इसके साथ ही पहले से ज्यादा दमनकारी उपाय करो। सभी मठों में चलाए जा रहे तथाकथित देशभक्तिपूर्ण शिक्षा अभियान के दौरान भिक्षुओं को दलाई लामा से दूरी बनाने को कहा जाता है। बहुत से भिक्षुओं को अस्थायी या स्थायी रूप से मठों में जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है और कुछ लामाओं को जेल में या पुनर्शिक्षा शिविर में डाल दिया गया है। आत्मदाह कर जान देने वाले लोगों के तथाकथित समर्थकों को जेल में डाल दिया जाता है जिनमें शियाहे के किसान दोरजी रिनछेन के करीबी छह लोग भी शामिल हैं।

चीन के शासक तिब्बत की रणनीति पर कोई सार्वजनिक बहस करने की इजाजत नहीं देते। यही नहीं, इस मसले को उठाने की हिम्मत भी बहुत कम चीनी लोग कर पाते हैं और वह भी हांगकांग में या विदेशी मीडिया संगठनों के द्वारा होता है। तिब्बती गीतकार सेरिंग वुएजर के पति लेखक वांग लिजियांग भी ऐसे ही कुछ बहादुर लोगों में से हैं। उनका मानना है कि तब तक कुछ बदलाव नहीं आने वाला जब तक पार्टी के प्रोपेगंडा मशीन में लगे हजारों अधिकारियों की जीविका दलाई लामा के खिलाफ दुष्प्रचार से चलती रहेगी। किताब के तिब्बती लेखक भी इसे इस तरह से बताते हैं, "हम सबके दिल में एक गांठ है। अधिकारी भिक्षुओं को बाहरी व्यक्ति की तरह देखते हैं। उनको अपने विचार व्यक्त नहीं करने दिया जाता और उनको राजनीतिक निर्णयों में भी शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाती।

तिब्बतियों की दुर्दशा का कोई हल है? लेखक का भी यह मानना है कि अब पुराने सामंतवादी तरह की व्यवस्था को वापस नहीं लाया जा सकता। तो आखिर इसका विकल्प क्या है? वह कहते हैं, "हमारे पास एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जरूरी नहीं कि यह पश्चिम के तरह का लोकतंत्र हो, लेकिन एक विशिष्ट तिब्बती स्वरूप वाला। अन्यथा हम बंद गली में ही पड़े रहेंगे।" ◆

तिब्बतन पॉलिटिकल एस्पिरेशन वर्सेज चाइनीज नेशनलिज्म

चीन अधिकृत तिब्बत में हालात के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी जागरूकता के बावजूद–अन्याय, मानवाधिकार के अत्याचार, सेंसरशिप और बीजिंग के विलोपन और उपनिवेशीकरण के कार्यक्रम के द्वारा व्यापक तौर पर तिब्बती संस्कृति का क्षरण–राष्ट्रीय और सांस्कृतिक आज़ादी का तिब्बती संघर्ष एक ऐसा विषय है जिसे सही तरीके से समझा नहीं गया है। समूचे तिब्बत में वर्ष 2008 में अचानक फैल गए तिब्बतियों के विरोध प्रदर्शन के राजनीतिक लक्ष्य और प्रकृति को अक्सर नजरअंदाज और गलत तरीके से पेश किया जाता है।

जैसा कि वारेन डब्ल्यू स्मिथ जूनियर की पुस्तक तिब्बत्स लास्ट स्टैंड में खुलासा किया गया है? वर्ष 2008 की तिब्बती जनक्रांति और चीन की इस पर प्रतिक्रिया, तिब्बती राष्ट्रीय पहचान (तिब्बत के आत्मनिर्धारण और स्वाधीनता के अधिकार के निर्विवाद तथ्य चीनी दमन के खिलाफ तिब्बती प्रतिरोध की निर्णायक विशेषताएं हैं।" यह एक विद्वतापूर्ण कृत्य है जिसमें उन्होंने कई तथ्यात्मक और जानकारीपूर्ण स्रोत (तिब्बती, चीनी, मानवाधिकार संगठनों, सरकार और मीडिया की खबरों) का इस्तेमाल किया है और चीन के अवैध कब्जे को चुनौती देने पर गोलियों, प्रताड़ना और जेल की सजा का सामना करने वाले तिब्बतियों के साहसी और प्रेरक कार्यों का विस्तृत ब्योरा और गहर आंतरिक जानकारी दी है।

वारेन स्मिथ साक्ष्यों के दुर्जेय व्यूह रचना से और बेहतर समझ एवं विश्लेषण के साथ जनक्रांति के बर्बर नतीजे को दर्शाते हैं जिसका कि तिब्बतियों को चीन के खूनी प्रतिक्रिया की वजह से सामना करना पड़ा है। वह इसके बाद होने वाले आतंक और दुर्व्यवहार के दस्तावेजों की पूरी सूची पेश करते हैं। हिंसा, सेंसरशिप, नस्लवाद, नियंत्रण और दुष्प्रचार का ऐसा वातावरण जिसे जर्मनी के नाजी या रूस के स्टालिन से कम नहीं समझा जा सकता और जिसे तिब्बतियों के विद्रोह को कुचलने और बीजिंग ओलंपिक की तैयारी अबोध तरीके से करने के लिए तैयार किया गया था।

लेखक ने बेहतरीन तरीके से दिखाया है कि बीजिंग ओलंपिक एक ऐसा आयोजन था जिसने चीन को तिब्बत पर अपन फर्जी दावे को फिर से दोहराने, कई तरह के प्रोपेगंडा की वजह से अंतरराष्ट्रीय जनमत में हेरफेर करने का मौका दिया और निर्वासित तिब्बती सरकार पर वह इस तरह से और दबाव बनाने में समर्थ हुआ जो कि बेसब्री से वार्ता प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रही थी। लेखक ने इन सबकी कुशलता से जांच की है और वह सार्थक स्वायत्तता के बदले चीन को संतुष्ट करने में लगे निर्वासित तिब्बती प्रशासन के जटिल और निरर्थक प्रयास पर भी नजर डालते हैं।

तिब्बती इतिहास के प्रख्यात जानकार, लेखक और रिसर्चर के रूप में वारेन डब्ल्यू स्मिथ के जाहिर विश्वसनीयता और विशेषज्ञता अलावा इस पुस्तक के द्वारा तिब्बत में स्वाधीनता की एक उत्कृष्ट भावना सामने आती है जिसे दबाया नहीं जा सकता। ठोस तथ्य यह हैं कि न केवल चीन तिब्बत की संप्रभुता से जबरन इनकार कर रहा है, बल्कि तिब्बतियों को आत्मनिर्धारण का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। साथ ही तिब्बत चीनी कब्जे के बावजूद एक विशिष्ट संस्कृति और देश बना हुआ है। इसलिए अचरज की बात नहीं कि वह तिब्बत के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पह. चान को मौजूदा और भविष्य के प्रयासों में एक स्थापित मुख्य परिक्षेत्र मानते हैं जिससे कम्युनिस्ट चीनी शासन वाले तिब्बत में अपरिहार्य रूप से बढ़ने वाले अंधकार के खिलाफ प्रतिरोध किया जा सकता है।

लेखक ने तिब्बत पर अपने पहले से उल्लेखनीय रचनात्मक कार्य के अलावा इस बार एक और प्रतिभावान उपलब्धि हासिल की है। तिब्बत के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक अस्तित्व के संघर्ष के परीक्षण में उन्होंने एक बेहतरीन और गहन आकलन पेश किया है। विस्तृत, राजनी. तिक समझ और गहन जानकारी वाली यह पुस्तक अनिवार्य रूप से पठनीय है और लेखक को इस बात के लिए बधाई देनी होगी कि उन्होंने वर्ष 2008 के तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति और इसके राजनीतिक एवं मानवीय परिणामों का ऐसा गहन लेखा–जोखा पेश किया है।

तिब्बती राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण मसलों को साफ तौर से बताने और उनको निर्धारित करने तथा तिब्बती प्रतिरोध की प्रकृति और लक्ष्य को तलाश करने के लिहाज से यह एक विशिष्ट पुस्तक है जो ऐसे लेखक के द्वारा जानकारी से भरी और समृद्ध की गई है जो मसले की वाजिब समझ रखता है। सतर्कता से तैयार अनुसंधान सामग्री के खजाने के साथ यह पुस्तक इस खुलासे के लिए ताजी सूचनाएं और विद्वतापूर्ण संदर्भ पेश करता है जो कि चीनी शासन के दमन और अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय और सांस्कृति विरोध में उल्लेखनीय हैं।

प्रस्तावना में लेखक द लिटिल बिग हॉर्न का हवाला देते हैं जिसमें कर्नल कस्टर के नेतृत्व वाली अमेरिकी घुड़सवार सेना को 1876 में सियोक्स और चेयेने इंडियंस के गठजोड़ ने घेरकर कर नरसंहार कर दिया था। इस घटना को 'विकास' के पश्चिम की तरफ विस्तार के खिलाफ देशज प्रतिरोध का अंत माना गया था। जैसा कि पुस्तक में कहा गया है, कुछ विशेषताओं के साझा होने के बावजूद तिब्बत में स्वाधीनता और राष्ट्र के संघर्ष की इससे तुलना करना न तो उपयुक्त होगा और न ही सही। समूचे अमेरिका में फैले विभिन्न गुटों के विपरीत तिब्बती ऐसी कई विशेषताओं को साझ करते हैं जिनकी वजह से उन्हें एक जनता कहा जा सकता हैः साझी भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास और सरकार का तंत्र। इसके अलावा तिब्बती बैलों और उन्मत घोड़ों पर सवार लोग नहीं बल्कि जानकार, शिक्षित और राजनीतिक रूप से प्रेरित ऐसे समुदाय हैं जो अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, तिब्बती स्वाधीनता की वकालत कर रहे हैं और चीन द्वारा तिब्बत पर फर्जी दावे के दुष्प्रचार का विरोध कर रहे हैं। लेखक का यह मानना है कि निर्वासित तिब्बती तिब्बत के इतिहास का एक सच्ची व्याख्या पेश कर सकते हैं और चीनी कब्जे, तिब्बती राष्ट्रीय पहचान की हताश करने वाली सच्चाई को बयान कर सकते हैं।

इस पुस्तक में दिए गए विषय पर अध्ययन के लिए यथार्थवादी नजरिए से सोचने और वस्तुनिष्ठता की जरूरत है और अंतिम पेज तक पाठक को कुछ और हासिल होने की उम्मीद बनी रहती है। शायद यह एक रोमानी उम्मीद होगी कि लिटिल बिग हॉर्न के करुणामयी नायकत्व के बिना तिब्बत के भीतर या बाहर कोई प्रतिरोध हो सकता है। वर्ष 2008 के तिब्बती राष्ट्रीय क्रांति को परिभाषित करने वाला निःस्वार्थ साहस और बलिदान अंतिम रवैया नहीं है, बल्कि यह तो एक निर्णायक और प्रेरक आयोजन था जिससे मौजूदा और भविष्य की तिब्बती पीढ़ी को यह दृढ़ता मिलेगी कि वे आज़ादी की लौ को जलाए रखें।

तो तिब्बत का अंतिम दांव क्या होगा? तिब्बती मसले का यदि कोई जानकारीपूर्ण और तथ्यात्मक समझ हासिल करना चाहता है तो 2008 की तिब्बती जनक्रांति और इस पर चीन की प्रतिक्रिया, तिब्बती जनता की राजनीतिक आकांक्षा, चीनी शासन को जायज ठहराने वाले उश्रृंखल राष्ट्रवाद, उसके दमन और दुष्प्रचार की मशीनरी और तिब्बत पर उसके निर्दयी कब्जे के बारे में पढ़ना चाहिए। यह तिब्बत के राजनीतिक इतिहास पर लिखने वाले सबसे प्रमुख लेखक की रोचक लेकिन निर्णायक रचना है। यह प्रेरक और कई मौकों पर दिल तोड़ने वाली भी लगती है। यह एक आसानी से समझने वाली, सुस्पष्ट शैली में लिखी गई जानकारीपूर्ण पुस्तक है। अगर किसी को मानवाधिकार, न्याय और तिब्बती जनता की स्वाधीनता में रुचि है तो उसे यह पुस्तक जरूर पसंद आएगी। ◆